

in regard to routes that are running at a loss?

**Shri Mohiuddin:** The difficulty arises that when a service is discontinued, there is demand for it. Of course, Government also keep in view the fact that important points which have been connected for long should continue to be so and the service should not be discontinued, as far as possible. As far as reducing the loss is concerned, I have already stated what we are trying to do.

**Shri Hem Barua:** The Minister has made a reference to increase in traffic. Since there has been an increase in passenger traffic of 20 per cent annually, may I know why the IAC has failed to make any profit? Do Government propose to hold a thorough probe into the working of IAC?

**Mr. Speaker:** The hon. Minister has given the reasons why losses are there.

**Shri Mohiuddin:** I will just clarify the point which has been misunderstood by the hon. Member. The loss incurred by IAC in 1957-58 was Rs. 103 lakhs and in 1958-59, Rs. 91 lakhs. The profit earned in 1959-60 was Rs. 7,81,000, in 1960-61 Rs. 4,69,000 and in 1961-62 it is expected that there will be a similar small profit.

### फसल का बीमा

३८३. श्री विभूति मिश्र : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फसलों का बीमा कराने के लिये जो प्रबन्ध किया जाने वाला था उस योजना पर कहां तक काम हुआ है ;

(ख) यह योजना कब से चालू हो जायेगी ; और

(ग) योजना की पूरी रूप रखा क्या होगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) से (ग) : पंजाब सरकार का राज्य में फसल बीमे के लिए एक पाइलट

योजना चालू करने का विचार है। वह इस योजना का ब्यौरा तैयार कर रही है और अन्तिम योजना भारत सरकार के पास अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इस अवस्था में यह कहना सम्भव नहीं है कि वह योजना कब से लागू होगी।

I shall read it in English also.

(a) to (c). The Punjab Government intend to introduce a pilot scheme for crop insurance in that State. Details of the scheme are being worked out by them and the final scheme has not so far been received by the Government of India. It is not possible to say at this stage when the scheme would be introduced.

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूँ कि केन्द्रीय सरकार विभिन्न सूबों में क्राप इन्श्योरेंस के लिए खुद कोई कार्रवाई कर रही है या विभिन्न सूबों को कोई मदद दे रही है ताकि वहां क्राप इन्श्योरेंस हो ?

श्री स० का० पाटिल : हाँ, जरूर थोड़ी बहुत मदद दे रही है। सन् १९४७ में उस ने एक स्पेशल आफिसर नियुक्त किया इस की जांच करने के लिये, और अभी सरकार ने एफ० ए० ग्रो० में भी उस की सर्विसेज मांगी हैं और उस का उपयोग किया जाता है। लेकिन असल में यह काम राज्य सरकार का है कि वह तय करे कि इस को लागू करना है या नहीं। गवर्नमेंट आफ इंडिया इस में इतनी मदद दे रही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्स्पेंस वगैरह जो आयेगा वह उस का आधा हिस्सा देगी।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूँ कि केन्द्रीय सरकार ने पहले गल्ले के सामान का इन्श्योरेंस करने की हिदायत दी है या कौश क्राप का इन्श्योरेंस करने की हिदायत दी है।

श्री स० का० पाटिल : पहले तो क्राप इन्श्योरेंस की योजना है। गल्ले की चीज तो दूसरी है। पंजाब में दो ग्रेन हैं, इफ आई मिस्टेक नाट, गेहूँ और उस के साथ चना और

टू कैश क्राप्स हैं, शुगर केन और काटन यानी कपास ।

**डा० गोबिन्द दास :** अभी मंत्री जी ने यह कहा कि सन् १९४७ में ही सरकार ने इस सम्बन्ध में एक अफसर की नियुक्ति की थी । इस को इतने वर्ष हो गये । तो क्या पंजाब के सिवा और किसी राज्य में इस के सम्बन्ध में कुछ हो रहा है ? और अगर हो रहा है तो कहां कहां हो रहा है ? साथ ही इस फसल के बीमे के साथ बैलों के बीमे का भी कोई विचार किया जा रहा है, जिन का फसलों से बहुत सम्बन्ध है ?

**श्री स० का० पाटिल :** ये दो सवाल अलग-अलग हैं ।

**अध्यक्ष महोदय :** बैलों को तो रहने दीजिए ।

**श्री स० का० पाटिल :** बैलों का तो विचार इस में नहीं है । यह तो क्राप इश्योरेंस का सवाल है । इस में बैल नहीं आते हैं । उन का तो इन्श्योरेंस हो सकता है, लेकिन वह अलग चीज है । क्राप इश्योरेंस के लिए स्टेट्स इसलिये तैयार नहीं हैं क्योंकि उन को यह मालूम नहीं है कि इस में कितना खर्चा आयेगा । उस में जो एक्चुरियल स्टटिस्टिक्स वगैरह चाहियें वह हमारे पास नहीं हैं और जब तक नहीं हैं तो इस प्रकार की चीज में यकायक पड़ना स्टेट के लिए तो कठिन है । इसलिए उस का एक्सपेरीमेंट वगैरह करना चाहिये । मैं मानता हूं कि सब से पहले पंजाब गवर्नमेंट इस काम के लिए सामने आई है । वह एक्सपेरीमेंट करे और सफल हो तो न केवल पंजाब में बल्कि और प्रांतों में भी वह शुरू किया जायेगा ।

**श्री ज० ब० सिंह :** मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी कोई इस तरह की स्कीम बनाई है कि क्राप इश्योरेंस किया जाये ?

**श्री स० का० पाटिल :** उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई ऐसी स्कीम अभी तक तो हमारे पास नहीं भेजी है ।

**अध्यक्ष महोदय :** एक बात मुझे कहनी है । जब मिनिस्टर यह जवाब दे कि मेरे पास सिर्फ पंजाब से ही यह स्कीम आयी है तो इस से जाहिर है कि और किसी स्टेट से नहीं आई है । ऐसी हालत में किसी मेम्बर का यह सवाल करना कि क्या राजस्थान से भी आई है या उत्तर प्रदेश से भी आई है, इस से कोई फायदा नहीं होता । और न इस से कोई खास इनफार्मेशन मिलेगी ।

**श्री स० मो० बनर्जी :** यह तो पूछ सकते हैं कि दूसरे राज्यों से क्यों नहीं आई ।

**अध्यक्ष महोदय :** अगर आप उस दूसरी स्टेट से ही पूछें तो ज्यादा अच्छा हो कि आप ने क्यों नहीं भेजी, बनिस्वत सेंटर से पूछने के कि क्यों नहीं आई ।

**श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :** क्या मंत्री महोदय कृपा कर के बतायेंगे कि पंजाब से जो स्कीम आई है उस में क्या लिखा है ?

**अध्यक्ष महोदय :** जितना लिखा हुआ है वह तो उन्होंने बताया ।

**Shrimati Yasoda Reddy:** Apart from the scheme submitted by the Punjab Government, I would like to know from the hon. Minister of Food and Agriculture whether the Government of India, as a matter of policy is thinking of introducing a general scheme of crop insurance in States where famine has become a regular feature. I just would like to know whether they intend to have any such policy because in some States there are districts having famine almost every year.

**Mr. Speaker:** Besides being long, the question is too wide.

**Shri S. K. Patil rose—**

**Shrimati Yasoda Reddy:** The hon. Minister is prepared to answer.

**Mr. Speaker:** Order, order. Shri Yadav.

**श्री रामसेवक यादव :** मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो पंजाब से स्कीम आई है उस के बारे में दूसरे राज्यों को भी लिखा गया है या नहीं और यदि लिखा गया है तो उन का क्या जवाब आया है ?

**श्री स० का० पाटिल :** वह तो सब को मालूम है, उस की अखबारों में चर्चा हुई है । हमारी एग्जीक्यूटिव कानफरेंसों में उस की चर्चा होती है और वह सब को मालूम है । मैं समझता हूँ कि यह काम आहिस्ता-आहिस्ता होगा । पंजाब में यह काम सफल हो गया तो दूसरे प्रान्तों में वह शुरू होगा ।

**श्री शिव नारायण :** क्या सरकार मेहरबानी कर के बतायेगी कि क्या इस स्कीम को भारत के अन्य प्रान्तों में भी लांच किया जायेगा ?

**अध्यक्ष महोदय :** यह सवाल बार-बार किया जाता है । मगर वह इस में नहीं आता ।

#### Iduky Hydro-Electric Project

+

\*384. { **Shri Vasudevan Nair:**  
**Shri Warior:**  
**Shri Kappen:**

Will the Minister of **Irrigation and power** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 256 on the 28th March, 1962 and be pleased to state:

(a) whether any agreement has been reached between Madras and Kerala Governments as to the utilization of the Iduky waters;

(b) if so, whether the work of the Iduky project will be started forthwith; and

(c) whether the necessary foreign exchange has been provided for the scheme?

**The Minister of Irrigation and Power (Hafiz Mohammad Ibrahim):** (a) and (b). No; Sir.

(c) It is too early to consider the question of providing foreign exchange for the Scheme.

**Shri Vasudevan Nair:** The Chief Minister of the Kerala Government stated in the State Assembly recently that there was no outstanding dispute as far as the Iduky waters were concerned between the Kerala Government and the Madras Government. May I know whether the Government of India has taken note of this statement of the Chief Minister of the Kerala Government, and if so, what is the reaction of the Government of India to it?

**Hafiz Mohammad Ibrahim:** The statement to which the hon. Members is referring has not come to my notice personally, but as far as the dispute is concerned, that is there. The differences are there between the two States in regard to the utilisation of the waters of the Iduky river. Some of it is wanted by Madras, to which the other State is not agreeing.

**Shri Vasudevan Nair:** What are the steps being taken by the Central Government to see that this dispute is settled at an early date and that the work on this project is taken up?

**Hafiz Mohammad Ibrahim:** If you permit me Sir this is half a page and I might read it out here. That will disclose the whole thing to the hon. Member and probably further questions also may not arise.

**Mr. Speaker:** It may be too long. I am afraid of so many pages. I cannot allow that but if he can give a summary of it just in a few words I can allow it. The hon. Member wants to know whether the Central Government is doing anything to get that dispute resolved between the two States.